भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3008

19 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

उचित मूल्य की दुकानों की आय

3008. श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) की आय बढ़ाने और उत्पादों की संख्या में वृद्धि करने के लिए निजी कंपनियों के साथ सहयोग करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) किन-किन राज्यों में जन पोषण केन्द्रों (जेपीके) के आधुनिकीकरण की प्रायोगिक परियोजना आंरभ की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा जन पोषण केन्द्रों के मॉडल का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ग): भारत सरकार, राज्यों और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के सहयोग से उचित दर की दुकानों (एफपीएस) को पोषणयुक्त वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए गैर-पीडीएस वस्तुओं के लिए चालान क्रेडिट तक पहुंच प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान कर रही है। इसके लिए, सिडबी ने एक कस्टमाइज्ड ऐप-एफपीएस सहाय विकसित किया है जो कार्यशील पूंजी के लिए ऋण प्रदान करता है। सिडबी ने बी2बी ऑनलाइन थोक विक्रेता एग्रीगेटर्स के साथ समझौता किया है ताकि एफपीएस डीलर इस सुविधा का लाभ उठा सकें। इन एफपीएस (जिन्हें जन पोषण केंद्र-जेपीके भी कहा जाता है) के पास ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वयं को पंजीकृत करने और एफपीएस सहायता का उपयोग करने के विकल्प हैं। वैकल्पिक रूप से, एफपीएस/जेपीके स्थानीय थोक विक्रेताओं/वितरण एजेंसियों के माध्यम से गैर-पीडीएस वस्तुएं भी प्राप्त कर रहे हैं।

वर्तमान में, गुजरात (अहमदाबाद), तेलंगाना (हैदराबाद), राजस्थान (जयपुर) और उत्तर प्रदेश (गाजियाबाद) राज्यों/जिलों में जन पोषण केंद्र (जेपीके) प्रायोगिक अध्ययन शुरू किया गया है। इस प्रायोगिक अध्ययन के तहत 60 एफपीएस डीलरों (पहचाने गए राज्यों/जिलों से प्रत्येक में 15 एफपीएस डीलर) को जन पोषण केंद्र में परिवर्तित कर दिया गया है।

राज्यों को अपने राज्यों में जेपीके मॉडल को वांछित संख्या तक बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

*****